भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 834
07 फरवरी, 2023 को उत्तरार्थ

विषय:कृषि सुधार

834. डॉ. पोन गौतम सिगामणि:
श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:
श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि क्षेत्र में सुधार अभी भी अधूरे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और भविष्य में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग)क्या यह सचहै कि जब तक देश में आधुनिक भूमि प्रणालियां और भूमि अभिलेख नहीं होंगे, तब तक देश कृषि क्षेत्र में सुधार नहीं कर पाएगा;

(घ) क्या यह सच है कि कृषि के लिए सुधार एजेंडा न केवल 1991 से लम्बित है, बल्कि यह आज भी लम्बित है, बल्कि यह आज भी लम्बित है; और

(ड.) क्या यह भी सच है कि कृषि में बदलाव लाने के लिए किसानों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त किया जाना चाहिए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ङ): कृषि राज्य का विषय है, राज्य कृषि से संबंधित राज्यीय विशेष मुद्दों का प्रचार-प्रसार तथा उद्धार के लिए प्रभावी उपाय करते हैं। तथापि, भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों और बजटीय सहायता तथा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। भारत सरकारकी विभिन्न स्कीमें/कार्यक्रम का उद्देश्य उत्पादन वृद्धि, लाभकारी रिटर्न तथा किसानों को आय सहायता करके किसानों का कल्याण करना है। इन हस्तक्षेपों के कारण वर्षों से कृषि उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। 2021-22 में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन

315.72 मीट्रिक टन और बागवानी फसलों का 342.33 मीट्रिक टन हुआ था। भूमि संसाधन विभाग देश भर में भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण के लिए एक कार्यक्रम भी लागू कर रहा है।

सरकार ने किसानों के लिए उच्च आय हेतु कई विकासकारी कार्यक्रमों, योजनाओं, सुधारों और नीतियों को अपनाया/कार्यान्वित किया है। इसमें शामिल निम्नलिखित हैं:

1. **बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि**

   वर्ष 2013-14 में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (डेयर सहित) और मात्स्यिकी, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के लिए बजट आवंटन केवल 30223.88करोड़ रुपये था। इसे वर्ष 2022-23 में 4.59गुना से अधिक बढ़ाकर 138920.93करोड़ रुपयेकर दिया गया है।

2. **पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता**

   वर्ष2019 में पीएम-किसान योजना का शुभारंभ - यह 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये प्रदान करने वाली एक आय सहायता योजना है। अब तक लगभग 11 करोड़ पात्र किसान परिवारों को 2.24 करोड़ रूपए से अधिक धनराशि जारी की गई है।

3. **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)**

   छह वर्ष - वर्ष 2016 में पीएमएफबीवाई को किसानों के लिए उच्च प्रीमियम दरों और कैपिंग के कारण बीमित राशि में कमी की समस्याओं का समाधान करने हेतु शुरू किया गया था। कार्यान्वयन के पिछले 6 वर्षों में - 38 करोड़ किसान आवेदकों को नामांकित किया गया है और 12.37 करोड़ (अनंतिम) से अधिक किसान आवेदकों के दावे प्राप्त हुए हैं। इस अवधि के दौरान किसानों द्वारा उनके प्रीमियम के रूप में लगभग 25,252 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था जिसकी तुलना में उन्हें 1,30,015 करोड़ रुपये (अनंतिम) से अधिक के दावों का भुगतान किया गया है। इस प्रकार किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रत्येक 100 रुपये के प्रीमियम के लिए, उन्हें दावों के रूप में लगभग 514 रुपये प्राप्त हुए हैं।

4. **कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण**

   i. संस्थागत ऋण की पहुंच को वर्ष 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में 18.5 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है।

   ii. केसीसी के माध्यम से अब पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को भी उनकी अल्पकालिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 4% ब्याज पर रियायती संस्थागत ऋण का लाभ प्रदान किया जाता है।

   iii. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से सभी पीएम-किसान लाभार्थियों को कवर करते हुए रियायती संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया गया है। दिनांक 23.12.2022 की स्थिति के अनुसार, इस अभियान के हिस्से के रूप में 4,49,443 करोड़ रुपये की स्वीकृत ऋण सीमा के साथ 387.87 लाख नए केसीसी आवेदनों को मंजूरी दी गई है।

5. **न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन लागत का डेढ़ गुना तय करना -**

i. सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत के प्रतिफल के साथ सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की है।

ii. धान (सामान्य) के लिए एमएसपी को वर्ष 2013-14 में 1310 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में 2040 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

iii. गेहूं के एमएसपी को वर्ष 2013-14 में 1400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में 2125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया।

6. देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना

i. देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015-16 में परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) शुरू की गई थी। 32384 क्लस्टर गठित किए गए हैं और 6.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है जिससे 16.19 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 123620 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया और प्राकृतिक खेती के अंतर्गत 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड के किसानों ने नदी जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ-साथ अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए गंगा नदी के दोनों ओर जैविक खेती शुरू की है।

ii. सरकार का भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) योजना के माध्यम से सतत प्राकृतिक कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव है। प्रस्तावित योजना का उद्देश्य खेती की लागत में कटौती करना, किसानों की आय में वृद्धि करना और संसाधन संरक्षण और सुरक्षित एवं स्वस्थ मृदा, पर्यावरण और भोजन सुनिश्चित करना है।

iii. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) शुरू किया गया है। इसके तहत 379 किसान उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया है जिसमें 189039 किसान शामिल हैं और 172966 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।

7. प्रति बूंद अधिक फसल

प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना वर्ष 2015-16 के में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करना और उत्पादकता में वृद्धि करना है। वर्ष 2015-16 से अब तक पीडीएमसी योजना के माध्यम से 69.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया है।

8. सूक्ष्म सिंचाई कोष

नाबार्ड के साथ 5000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निधि का एक सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया है। वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में इस कोष में निधियों की मात्रा को बढ़ाकर 10000 करोड़ रुपये किया जाना है। इसके तहत 17.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों को कवर करने वाली 4710.96 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

9. किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का संवर्धन

i. माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा **दिनांक29 फरवरी, 2020 को वर्ष 2027-28** तक 6865 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ नए 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की गई।

ii. दिनांक 30.11.2022 तक की स्थिति के अनुसार, नई एफपीओयोजना के तहत 4028 एफपीओ पंजीकृत किए गए हैं।

iii. दिनांक 30.11.2022 तक की स्थिति के अनुसार, 1415 एफपीओ को 53.4 करोड़ रूपए का साम्या अनुदान जारी किया गया है।

iv. दिनांक 12.12.2022 तक की स्थिति के अनुसार, 447 एफपीओ को 78 करोड़ रूपए का ऋण गारंटी कवर जारी किया गया है।

10. वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में **राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)** शुरू किया गया है ताकि परागण के माध्यम से फसल उत्पादकता में वृद्धि की जा सके और आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहद उत्पादन में वृद्धि की जा सके। मधुमक्खी पालन क्षेत्र के लिए वर्ष 2020-2021 से 2022-2023 की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष **2020-21 और 2021-22** के दौरान अब तक एनबीएचएम के तहत वित्त पोषण हेतु लगभग **139.23**करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करते हुए **114**परियोजनाएं अनुमोदित/स्वीकृत की गई हैं।

11. कृषि यंत्रीकरण

कृषि को आधुनिक बनाने और कृषि कार्यों में कठोर श्रम को कम करने के लिए कृषि यंत्रीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2014-15 से मार्च, 2022 की अवधि के दौरान कृषि यंत्रीकरण के लिए 5490.82 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। किसानों को राजसहायता आधार पर 13,88,314 मशीनें और उपकरण प्रदान किए गए हैं। किसानों को किराये पर कृषि मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 18,824 कस्टम हायरिंग केंद्र, 403 हाई-टेक हब और 16,791 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं। वर्तमान वर्ष अर्थात 2022-23 के दौरान अब तक राजसहायता पर लगभग 65302 मशीनों के वितरण, 2804 सीएचसी, 12 हाईटेक हब और 1260 ग्राम स्तरीय फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना के लिए 504.43 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

12. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना

पोषक तत्वों के ईष्टतम उपयोग के लिए वर्ष 2014-15 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। किसानों को निम्नलिखित संख्या में कार्ड जारी किए गए हैं।

(i) चक्र-I (2015 से 2017) - 10.74 करोड़

(ii) चक्र-II (2017 से 2019) - 12.19 करोड़

(iii) मॉडल ग्राम कार्यक्रम (2019-20) - 23.71 लाख

(iv) वर्ष 2020-21 में- 11.52 लाख

13. **राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) विस्तार प्लेटफार्म की स्थापना करना**

(i) 22 राज्यों और 03 संघ राज्य क्षेत्रों की 1260 मंडियों को ई-नाम प्लेटफार्म से जोड़ा गया है।

(ii) दिनांक 29.11.2022 तक की स्थिति के अनुसार, ई-नाम पोर्टल पर 1.74 करोड़ से अधिक किसानों और 2.37 लाख व्यापारियों को पंजीकृत किया गया है।

(iii) दिनांक 29.11.2022 तक की स्थिति के अनुसार, ई-नाम प्लेटफॉर्म पर लगभग 2.33 लाख करोड़ रूपए के मूल्य वाली कुल 6.8 करोड़ मीट्रिक टन मात्रा व 20.05 करोड़ (बांस, पान के पत्ते, नारियल, नींबू और स्वीट कॉर्न) का समग्र रूप से व्यापार दर्ज किया गया है।

(iv) दिनांक 01.12.2022 की स्थिति के अनुसार ई-नाम प्लेटफॉर्म पर मूल्यांकन करने के लिए 203 कृषि एवं संबद्ध उत्पादों के लिए व्यापारी योग्य मापदंड बनाए गए हैं।

14. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम - एनएमईओ को 11,040 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। इससे अगले 5 वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों में 3.28 लाख हेक्टेयर और शेष भारत में 3.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ऑयल पाम वृक्षारोपण के तहत 6.5 लाख हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र शामिल किया जाएगा। यह मिशन उद्योग द्वारा सुनिश्चित खरीद से जुड़े किसानों को सरल मूल्य निर्धारण सूत्र के साथ ताजे फलों के गुच्छों (एफएफबी) को व्यवहारिक मूल्य प्रदान करने पर केंद्रित है।

15. कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)

वर्ष 2020 में एआईएफ की स्थापना के बाद से, इस योजना ने 19191 से अधिक परियोजनाओं के लिए देश में 14170 करोड़ रुपये के कृषि बुनियादी ढांचे को मंजूरी दी है। इस योजना की सहायता से विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं का सृजन किया गया है और कुछ अवसंरचना पूरी होने के अंतिम चरण में हैं। इन बुनियादी अवसंरचनाओं में 8215 गोदाम, 3076 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, 2123 कस्टम हायरिंग केंद्र, 992 छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयां, 728 शीतागार परियोजनाएं, 163 परख इकाइयां और लगभग 3632 अन्य प्रकार की फसलोपरांत प्रबंधन परियोजनाएं तथा सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियां शामिल हैं।

16. कृषि उपज लॉजिस्टिक में सुधार, किसान रेल की शुरूआत।

रेल मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से जल्द खराब होने वाली कृषि वस्तुओं की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए किसान रेल शुरू की गई है। पहली किसान रेल जुलाई, 2020 में शुरू की गई थी। दिनांक 31 दिसंबर, 2022 तक 167 मार्गों पर 2359 किसान रेल सेवाएं संचालित की गई हैं।

17. एमआईडीएच - क्लस्टर विकास कार्यक्रम:

क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) को बागवानी समूहों की भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने और उत्पादन पूर्व, उत्पादन, फसल कटाई के बाद, लॉजिस्टिक, ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों के एकीकृत और बाजार-आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (डीएएंडएफडब्ल्यू) ने 55 बागवानी क्लस्टरों की पहचान की है, जिनमें से 12 को सीडीपी के प्रायोगिक चरण के लिए चुना गया है।

18. कृषि और संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप व्यवस्था का निर्माण

वित्त वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान डीएएंडएफडब्ल्यू के नालेज पार्टनर और कृषि व्यवसाय इनक्यूबेटरों द्वारा अब तक1055 स्टार्टअप का अंतिम रूप से चयन किया गया है। डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा अनुदान सहायता के रूप में संबंधित ज्ञान साझेदारों (केपी) और आरकेवीवाई-रफ्तार कृषि व्यवसाय इंक्यूबेटर (आर-एबीआई) को इनस्टार्टअप के वित्त पोषण के लिए 66.83 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता जारी की गई है।

19. कृषि और संबद्ध कृषि-वस्तुओं के निर्यात में उपलब्धि

देश में कृषि और संबद्ध वस्तुओं के निर्यात में जोरदार वृद्धि देखी गई है। पिछले वर्ष 2020-21 की तुलना में, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में निर्यात वर्ष 2020-21 **के 41.86** बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष **2021-22 में 50.24**बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है अर्थात **19.99%** की वृद्धि हुई है।

*****